



The Madhya Pradesh Ladli Laxmi (Balika Protsahan) Act, 2018

Act 29 of 2018

Keyword(s):

Beneficiary, Certificate of Assurance, Family Planning, Female Child, Fund, Ladli Laxmi Yojna, Parents, Scheme

Amendment appended: 21 of 2022

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 431]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 जुलाई 2018—श्रावण 9, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2018

क्र. 12719-259-इक्कीस-अ (प्रा.)अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16 जुलाई 2018 को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २९ सन् २०१८

मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) अधिनियम, २०१८

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.
३. रजिस्ट्रीकरण के लिए पूर्ववर्ती शर्तें.
४. हितग्राहियों का रजिस्ट्रीकरण तथा सत्यापन.
५. लाभ.
६. मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना निधि का गठन.
७. निदेश जारी करने की शक्ति.
८. विवाद समाधान.
९. नियम बनाने की शक्ति.
१०. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.
११. व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २९ सन् २०१८

मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) अधिनियम, २०१८

[दिनांक १६ जुलाई, २०१८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ३१ जुलाई, २०१८ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

बालिकाओं को विशेष अधिकार उपलब्ध कराना जिससे कि वे अपनी क्षमताओं को साकार करने में समर्थ हो सकें, ऐसा सामाजिक परिवेश सृजित करना जिसमें माता-पिता और समाज बालिकाओं का स्नेहपूर्ण संरक्षण एवं देखभाल करें और उससे संसक्त तथा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार
और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) अधिनियम, २०१८ है.
- (२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.
- (३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) "हितग्राही" से अभिप्रेत है, ऐसी बालिका जो रजिस्ट्रीकृत हो तथा योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने की हकदार हो;
 - (ख) "आश्वासन प्रमाण-पत्र" से अभिप्रेत है, हितग्राही के पक्ष में लाभ अधिप्रमाणित तथा सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया प्रमाण-पत्र;
 - (ग) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, योजना के अधीन प्रलाभों को मंजूर करने के लिए कलक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी;
 - (घ) "परिवार नियोजन" से अभिप्रेत है, बालिका की माता की दशा में ट्यूबेक्टोमी शल्य क्रिया और पिता की दशा में वेसेक्टोमी शल्य क्रिया अथवा अन्य विहित उपाय;
 - (ङ) "बालिका" से अभिप्रेत है, ऐसी बालिका जो धारा ५ के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हो;
 - (च) "निधि" से अभिप्रेत है, धारा ६ के अधीन गठित निधि;
 - (छ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
 - (ज) "लाडली लक्ष्मी योजना" से अभिप्रेत है, प्रशासनिक आदेश द्वारा १ अप्रैल, २००७ से राज्य में चल रही योजना;
 - (झ) "माता-पिता" से अभिप्रेत है, बालिका के नैसर्गिक माता-पिता या दत्तक पुत्री की दशा में उसके दत्तक माता-पिता और यदि माता-पिता जीवित नहीं हैं तो उसका विधिक संरक्षक या अनाथ बालिका की दशा में उस अनाथालय या शिशु संरक्षण संस्था का अधीक्षक, जहां कि बालिका को प्रवेश दिया गया है;

(अ) "रजिस्ट्रीकरण केन्द्र" से अभिप्रेत है, हितग्राहियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए स्थापित केन्द्र;

(ट) "योजना" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन धनीय और अन्य लाभ, यदि कोई हों, उपलब्ध कराने के उपबंध.

३. कोई भी बालिका इस योजना के अधीन रजिस्ट्रीकरण की हकदार होगी, यदि—

रजिस्ट्रीकरण के लिए पूर्ववर्ती शर्तें.

(एक) उसके माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं और आय-कर दाता नहीं हैं और यदि रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् माता-पिता आयकर दाता बन जाते हैं तो भी बालिका इस योजना के अधीन लाभ प्राप्त करती रहेगी;

(दो) माता-पिता ने द्वितीय जीवित बच्चे के पश्चात् परिवार नियोजन अपना लिया है;

(तीन) वह आंगनवाड़ी केन्द्र में नामांकित है; और

(चार) वह किसी ऐसी अन्य शर्त की पूर्ति करती हो, जो कि विहित की जाए.

४. (१) माता-पिता, बालिका के जन्म या दत्तकग्रहण या उत्तराधिकार के एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकरण केन्द्र में रजिस्ट्रीकरण के लिए ऐसी रीति में आवेदन करेंगे जैसी की विहित की जाए.

हितग्राहियों का रजिस्ट्रीकरण तथा सत्यापन.

(२) रजिस्ट्रीकरण केन्द्र का भारसाधक अधिकारी आवेदन के प्राप्त होने पर, उसमें अंतर्विष्ट विषय-वस्तु का सत्यापन करेगा तथा सक्षम प्राधिकारी के पास उसे अग्रेषित करेगा.

(३) सक्षम प्राधिकारी उप-धारा (२) के अधीन भारसाधक अधिकारी से आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् या तो उसे दर्ज करेगा और आश्वासन प्रमाण-पत्र जारी करेगा या आवेदन को अस्वीकार करेगा.

५. (१) हितग्राही धारा ४ के अधीन जारी आश्वासन प्रमाण-पत्र के अनुसार एक लाख अठारह हजार रुपए की राशि उपधारा (२) और (३) के अनुसार प्राप्त करने की हकदार होगी.

लाभ.

(२) हितग्राही निम्नलिखित राशि समय-समय पर प्राप्त करने का हकदार होगा,—

(एक)	कक्षा ६ठी में प्रवेश लेने के समय पर	रुपए २०००
(दो)	कक्षा ९वीं में प्रवेश लेने के समय पर	रुपए ४०००
(तीन)	कक्षा ११वीं में प्रवेश लेने के समय पर	रुपए ६०००
(चार)	कक्षा १२वीं में प्रवेश लेने के समय पर	रुपए ६०००

(३) हितग्राही को रुपए एक लाख की रकम का भुगतान २१ वर्ष की आयु पूर्ण करने पर किया जाएगा बशर्त कि वह यथाविहित शर्तों को पूर्ण करती हो.

६. (१) राज्य सरकार, मध्यप्रदेश लाइली लक्ष्मी योजना निधि के नाम से एक निधि गठित तथा संधारित करेगी, जिसे हितग्राहियों को धनीय लाभ संवितरण करने के लिए ऐसी रीति में उपयोजित की जाएगी जैसी की विहित की जाए.

मध्यप्रदेश लाइली लक्ष्मी योजना निधि का गठन.

(२) राज्य सरकार द्वारा, प्रति हितग्राही इस निधि में, उसके रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् तीस हजार रुपए जमा किए जाएंगे.

७. राज्य सरकार को इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए निदेश जारी करने की शक्ति होगी.

निदेश जारी करने की शक्ति.

विवाद समाधान.	८. कोई भी विवाद उद्भूत होने पर कलक्टर को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा.
नियम बनाने की शक्ति.	९. (१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी. (२) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.
कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.	१०. इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दो वर्ष के भीतर, राजपत्र में प्रकाशित इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत साधारण या विशेष आदेश द्वारा कठिनाई को दूर कर सकेगी.
व्यावृत्ति.	११. इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को राज्य की विद्यमान मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना के अधीन रजिस्ट्रीकृत समस्त बालिकाएं इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझी जाएंगी तथा योजना के अधीन लाभ की हकदार होंगी.

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2018

क्र. 12719-259-इक्कीस-अ (प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) अधिनियम, २०१८ (क्रमांक 29 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 29 OF 2018

THE MADHYA PRADESH LADLI LAXMI (BALIKA PROTSAHAN) ADHINIYAM, 2018

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Conditions precedent for registration.
4. Registration and verification of beneficiaries.
5. Benefits.
6. Constitution of Madhya Pradesh Ladli Laxmi Yojna Nidhi.
7. Power to issue directions.
8. Dispute resolution.
9. Power to make rules.
10. Power to remove difficulties.
11. Saving.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 29 OF 2018

THE MADHYA PRADESH LADLI LAXMI (BALIKA PRO TSAHAN) ADHINIYAM, 2018

[Received the assent of the Governor on the 16th July, 2018; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 31st July, 2018.]

An Act to provide for special rights to female children so as to enable them to realize their potential, create a social environment in which parents and society cherish female child and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-ninth year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Ladli Laxmi (Balika Protsahan) Adhiniyam, 2018.

**Short title,
extent and
commencement.**

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions

- (a) "beneficiary" means the female child who is registered and is eligible for benefits under the Scheme;
- (b) "certificate of assurance" means the certificate issued to authenticate and assure the benefit in favour of the beneficiary;
- (c) "competent authority" means an officer authorised by the Collector to grant sanction of the benefits under the Scheme;
- (d) "family planning" means tubectomy operation in case of the mother and vasectomy operation in case of the father of the female child or other prescribed measures;
- (e) "female child" means a female child who is eligible to get the benefits under section 5;
- (f) "Fund" means the fund setup under section 6;
- (g) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (h) "Ladli Laxmi Yojna" means the Scheme running in the State with effect from 1st April, 2007 by the administrative order;
- (i) "parents" means the natural parents of the female child or in case of adopted daughter, her adoptive parents, and if no parent is alive the legal guardian or in case of orphan, the superintendant of orphanage or child care institution where the female child is admitted;
- (j) "registration centre" means a centre established for the registration of the beneficiaries;
- (k) "Scheme" means the provisions of providing pecuniary and other benefits, if any, under this Act and the rules made thereunder.

3. A female child shall be entitled to registration under the Scheme if:

- (i) the parents are bonafide residents of Madhya Pradesh and are not income tax payee, in case the parents have become income tax payee after the registration, the female child shall continue to get the benefits under the Scheme;

**Conditions
precedent for
registration.**

- (ii) the parents have adopted family planning after second surviving child;
- (iii) she is enrolled in the Aaganwadi centre; and
- (iv) she fulfils any other condition that may be prescribed.

Registration and verification of beneficiaries.

4. (1) The parent shall submit application for registration in such manner as may be prescribed at the registration centre within a year of birth or adoption or succession of successor female child.

(2) The officer incharge of registration centre shall on receipt of the application, verify the contents therein and shall forward the same to the competent authority.

(3) The competent authority shall after receiving the application from the officer incharge under sub-section (2) above, either register and issue assurance certificate or reject the application.

Benefits

5. (1) The beneficiary shall be entitled to a sum of one lac eighteen thousand rupees under sub-sections (2) and (3), as per the certificate of assurance issued under section 4.

(2) The beneficiary shall be entitled to receive the following sums from time to time as below :—

(i)	At the time of admission to class 6th	—	Rs. 2000
(ii)	At the time of admission to class 9th	—	Rs. 4000
(iii)	At the time of admission to class 11th	—	Rs. 6000
(iv)	At the time of admission to class 12th	—	Rs. 6000

(3) The beneficiary shall be paid an amount of one lac rupees on attaining the age of 21 years provided she fulfils the conditions as prescribed.

Constitution of Madhya Pradesh Ladli Laxmi Yojna Nidhi.

6. (1) The State Government shall constitute and maintain a Fund known as Madhya Pradesh Ladli Laxmi Yojna Nidhi which shall be utilized for disbursing pecuniary benefits to the beneficiary in such manner as may be prescribed.

(2) A sum of thirty thousand rupees shall be deposited by the State Government in the Fund for each beneficiary after her registration.

Power to issue directions.

7. The State Government shall have powers to issue directions for carrying out the provisions of this Act and the rules made thereunder.

Dispute resolution

8. Any dispute arising shall be referred to the Collector whose decision shall be final.

Power to make rules.

9. (1) The State Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

Power to remove difficulties.

10. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, within two years of the commencement of this Act, by general or special order, published in the official Gazette, not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty.

Saving

11. All female children registered under the Madhya Pradesh Ladli Laxmi Yojna of the State prevailing as on the date of commencement of this Act shall be deemed to have been registered under this Act and shall be entitled to the benefit under the Scheme.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 549]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2022—आश्विन 12, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2022

क्र. 14953-244-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 3 अक्टूबर 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् २०२२

मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) संशोधन अधिनियम, २०२२

[दिनांक ३ अक्टूबर, २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ४ अक्टूबर, २०२२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) अधिनियम, २०१८ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) संशोधन अधिनियम, २०२२ है.
(२) यह इसके मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ५ का स्थापन.

२. मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) अधिनियम, २०१८ (क्रमांक २९ सन् २०१८) की धारा ५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

लाभ.

"५. (१) हितग्राही, समय-समय पर इस उपधारा और उपधारा (२) के अधीन निम्नानुसार एक लाख तैंतालीस हजार रुपए की कुल राशि प्राप्त करने की हकदार होगी:-

(एक)	कक्षा ६ठीं में प्रवेश लेने के समय पर	—	रुपए २०००
(दो)	कक्षा ९वीं में प्रवेश लेने के समय पर	—	रुपए ४०००
(तीन)	कक्षा ११वीं में प्रवेश लेने के समय पर	—	रुपए ६०००
(चार)	कक्षा १२वीं में प्रवेश लेने के समय पर	—	रुपए ६०००
(पांच)	कक्षा १२वीं के पश्चात् स्नातक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम (न्यूनतम दो वर्ष की अवधि) में प्रवेश लेने के समय पर.	—	रुपए २५,००० (पाठ्यक्रम अवधि के प्रथम तथा अंतिम वर्ष में दो बराबर किस्तों में).

- (२) हितग्राही इस शर्त के अधीन रहते हुए कि वह कक्षा १२वीं की परीक्षा में उपस्थित हुई है, और यदि वह विवाहित है तो ऐसा विवाह, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, २००६ (२००७ का ६) में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम आयु पूर्ण करने के पश्चात् किया गया था, २१ वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, एक लाख रुपए की रकम प्राप्त करने की हकदार होगी."

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2022

क्र. /244-इक्कीस-अ(प्रा.).-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) संशोधन अधिनियम, 2022 (क्रमांक 21 सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 21 OF 2022

**THE MADHYA PRADESH LADLI LAXMI (BALIKA PROTSAHAN) SANSHODHAN
ADHINIYAM, 2022**

[Received the assent of the Governor on the 3rd October, 2022; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 4th October, 2022.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Ladli Laxmi (Balika Protsahan) Adhinyam, 2018.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-third year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Ladli Laxmi (Balika Protsahan) Sanshodhan Adhinyam, 2022.

Short title and commencement.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. For Section 5 of the Madhya Pradesh Ladli Laxmi (Balika Protsahan) Adhinyam, 2018 (No. 29 of 2018), the following section shall be substituted, namely:—

Substitution of Section 5.

“5.(1) The beneficiary shall be entitled to receive a total sum of one lac forty three thousand rupees under this sub-section and sub-section (2) from time to time as below:—

Benefits.

(i)	At the time of admission to class 6 th	Rs. 2000
(ii)	At the time of admission to class 9 th	Rs. 4000
(iii)	At the time of admission to class 11 th	Rs. 6000
(iv)	At the time of admission to class 12 th	Rs. 6000
(v)	At the time of admission in graduation or professional course (minimum two years duration), after class 12 th .	Rs. 25000 (in two equal instalments in the first and last years of the course duration).

(2) The beneficiary shall be entitled to receive an amount of one lac rupees on attaining the age of 21 years subject to the condition that she has appeared in examination of class 12th, and if she is married then such marriage was solemnised after attaining the minimum age as specified in the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (No. 6 of 2007).”.